

ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली पर सहमति

कुलपतियों की बैठक

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राम नाईक के निर्देश पर शनिवार को हुई राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में प्रवेश और परीक्षा प्रणाली को ऑनलाइन करने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई। हालांकि, इस कार्य के लिए यूपी डेस्क की प्रस्तावित लागत पर आवासीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने सवाल उठाए।

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू-फारसी विश्वविद्यालय के सभागार में आहूत इस बैठक में 16 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद रहे। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु (सिद्धार्थनगर) के कुलपति डॉ. रजनीकांत पांडेय को छोड़कर ज्यादातर नवनियुक्त कुलपति ही इस बैठक से गैरहाजिर रहे। राजभवन की ओर से राज्यपाल के विशेष सचिव राजवीर सिंह राठौर ने बैठक में शिरकत की। उन्होंने कुलपतियों को कुलाधिपति की मंशा से अवगत कराया। मेजबान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. खान मसूद अहमद ने सभी कुलपतियों का स्वागत करते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर

- यूपी डेस्क के प्रतिनिधियों ने किया साफ्टवेयर का प्रदर्शन
- आवासीय विवि के कुलपतियों ने लागत पर सवाल उठाए

3 विश्वविद्यालयों में लागू है एकल खिड़की व्यवस्था

यूपी डेस्क की मदद से एकल खिड़की व्यवस्था प्रदेश के तीन राज्य विश्वविद्यालयों में पहले से लागू है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी और राजर्षि टंडन राज्य मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में इसके फायदे भी दिख रहे हैं। राजभवन की पहल पर शनिवार को हुई कुलपतियों की बैठक में यूपीडेस्क की ओर से ओम्नी-नेट टेक्नालॉजी के निदेशक आशीष श्रीवास्तव ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंपनी ने महाविद्यालयों का सम्बन्धीकरण, एकेडमिक कैलेंडर का संयोजन, प्रवेश प्रक्रिया, काउंसिलिंग, परीक्षा का संचालन एवं परीक्षाफल की घोषणा का कार्य संतोषजनक तरीके से संपादित किया। उन्होंने विश्वविद्यालयों की वेबसाइट केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाने, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया से जोड़ने पर भी जोर दिया।

हो रहे परिवर्तनों पर रोशनी डाली।

यूपी डेस्क के प्रतिनिधियों ने राज्य विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश और परीक्षा प्रणाली से संबंधित अपने साफ्टवेयर का प्रदर्शन किया। इसमें यह भी बताया कि इसके जरिए निर्धारित समय में पारदर्शी तरीके से प्रवेश किया जा सकता है। इसी तरह परीक्षा परिणाम भी समय से घोषित किए जा सकते हैं। कुलपतियों ने इस प्रक्रिया से पूर्व से अवगत होने और कुछ हद तक इस पर काम भी शुरू होने की जानकारी दी।

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अशोक

कुमार ने यूपीडेस्क की लागत को काफी अधिक बताया। उन्होंने कहा कि यूपीडेस्क का काम अपेक्षाकृत बेहतर और विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा है लेकिन निजी एजेंसियां यही काम काफी कम लागत में कर रही हैं। आवासीय विश्वविद्यालयों के सामने वित्तीय संकट भी होता है। इस कारण भी इसकी लागत कम किए जाने की जरूरत है।

कार्यक्रम में उर्दू अरबी फारसी विवि के कुलसचिव डा. नाजिम हुसैन अलजाफरी, डा. मारुख मिर्जा, डा. दुआ नकवी और डा. नीरज शुक्ला मौजूद थे।